*परिवर्तनकारी नवोन्मेष और समावेशी वृद्धि : कुछ यादृच्छिक विचार**

आर. गाँधी

मित्रो,

परिवर्तनकारी नवोन्मेष

2. मुझे विश्वास है कि अभी तक आप लोगों ने इन दो दिनों में कई बार सुना होगा कि परिवर्तनकारी नवोन्मेष है क्या। एक बार मैं पुनः इसी पर चर्चा करना चाहता हूँ, वास्तव में यह एक नवोन्मेषी उपाय है जो नया बाजार और वैल्यू नेटवर्क बनाने में मदद करता है और अंततोगत्वा, कई वर्ष बीतने के बाद पूर्व में उपयोग की जा रही प्रौद्योगिकी को बदलकर मौजूदा बाजार और वैल्यू नेटवर्क को परिवर्तित कर देता है।

3. परिवर्तनकारी नवोन्मेष सिद्धांत का उल्लेख हावर्ड बिजनेस स्कूल के क्लेटन क्रिस्टेनसन द्वारा अपनी किताब 'दि इनोवेटर्स डिलेमा' में किया गया था। श्री क्रिस्टेनसन ने इस शब्द का प्रयोग उन नवोन्मेषी उपायों की व्याख्या करने के लिए किया था जो नए वर्ग के ग्राहकों की खोज करके नए बाजार विकसित करते थे।

समोवशी वृद्धि और परिवर्तनकारी नवोन्मेष

4. एफआईबीएसी 2015 का मुख्य विषय 'परिवर्तनकारी नवोन्मेष के साथ-साथ समावेशी वृद्धि' था। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग क्षेत्र में इस प्रकार के नवोन्मेषों पर समुचित रूप से विचार-विमर्श किया होगा। अब मैं इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँः

5. मुझे लगता है कि परिवर्तनकारी नवोन्मेष और समावेशी वृद्धि के बीच एक नैसर्गिक संबद्धता और अनुरूपता है। परिभाषा के अनुसार दोनों अवधारणाओं का उद्देश्य पिरामिड की सबसे निचली सतह पर रहने वाले लोगों की स्थिति में सुधार लाना है। प्रायः परिवर्तनकारी नवोन्मेष के पहले ग्राहक बाजार के उस हिस्से से आते हैं जहां अप्रमाणित, प्रायः अपरिष्कृत उत्पाद होते हैं, वे अधिक मूल्य की मांग नहीं करते हैं। इसी तरह, समावेशी वृद्धि का लक्ष्य जनसंख्या का उपेक्षित भाग होता है। इसमें सतह के सभी लोगों को उत्पाद अथवा सेवाओं की पहुंच होती है जो पहले सिर्फ अधिक पैसा रखने वाले अथवा अधिक कुशलता रखने वाले लोगों की पहुंच में होते थे।

वित्तीय समावेशन और परिवर्तनकारी नवोन्मेष

6. समावेशी वृद्धि का मुख्य तत्व वित्तीय समावेशन है। यहां पर, हम परिवर्तनकारी नवोन्मेष की क्षमता की समीक्षा कर रहे हैं। इसमें कुछ हद तक, नई प्रौद्योगिकी, जिसमें मुख्यतः सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, उसमें से भी मोबाइल प्रौद्योगिकी शामिल है, का उपयोग किया जाता है और कारोबार प्रतिनिधि मॉडल जैसे नए कारोबारी मॉडल विकसित करके और सूक्ष्म वित्त जैसे नए उपायों में उधार देने जैसी प्रक्रियाओं और पुरानी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके किया जाता है।

7. इस नए कारोबारी मॉडल में रूपे कार्ड के अतिरिक्त एक नए प्रकार का खाता अर्थात बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) शामिल है। इसके परिणाम बहुत ही उत्साहजनक रहे हैं। मार्च 2015 के अंत में शाखारहित प्रणाली, जो मुख्यतः बीसी पर आधारित है, में गांवों में बैंकिंग आउटलेट की संख्या 5,04,139 थी और शहरी बीसी की संख्या 96847 थी। बीएसबीडी खातों की संख्या 398 मिलियन थी और उनमें शेष राशि ₹438.3 थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना ने इसमें विशेष वृद्धि की है।

8. समानंतर विकास आधार कार्ड जारी करने और बैंक खाते से कार्डों को संबंद्ध करने में हुआ है। यह पाया गया है कि अप्रैल 2015 तक 817.8 मिलियन से अधिक आधार कार्ड जारी किए गए हैं और अभी भी इसमें वृद्धि हो रही है। वास्तव में, यह एक अन्य मामला है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम निर्णय ने इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है और हमें आशा है कि जल्द ही इस मुद्दे को हल कर लिया जाएगा।

9. अन्य मूल तत्व मोबाइल प्रौद्योगिकी का उपयोग है। मोबाइल कवरेज का व्यापक विस्तार, भारी संख्या में लोगों के पास मोबाइल हैंडसेट होना, मोबाइल बैंकिंग उत्पाद और सेवाएं वित्तीय समावेशन और समावेशी वृद्धि में आगे बढ़ने के लिए सभी बहुत ही उपयोगी है।

* 25 अगस्त 2015 को एफआईबीएसी 2015 में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री आर. गाँधी द्वारा दिया गया समापन भाषण।

विनियमन में वित्तीय समावेशन और परिवर्तनकारी नवोन्मेष

10. अब, मैं समावेशी वृद्धि को आगे बढ़ाने के अंतिम लक्ष्य के साथ विनियमन के जरिए कुछ परिवर्तनकारी नवोन्मेष पर चर्चा करना चाहता हूँ। विशिष्ट श्रेणी के बैंक के शीर्ष के अंतर्गत उल्लिखित नवोन्मेषी उपायों का प्राथमिक उद्देश्य वित्तीय समावेशन है जो कि समावेशी वृद्धि से संबंधित रणनीतियों का एक महत्वपूर्ण भाग है।

विशिष्ट श्रेणी के बैंक

11. विशिष्ट श्रेणी के बैंक की अवधारणा पर पहली बार चर्चा 2007 में हुई थी; किंतु ऐसा महसूस किया गया था कि इस प्रकार के बैंकों के लिए वह सही समय नहीं था। उसके बाद, इस अवधारणा की चर्चा एक बार फिर अगस्त 2013 में उस समय हुई जब भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'भारत में बैंकिंग संरचना - भावी उपाय' विषय पर लेख प्रकाशित किया गया। उस लेख में बैंकिंग संरचना, बैंकों को लाइसेंस और बैंकिंग मॉडल के अनेक पक्षों पर विचार किया गया और कई बैंकों के लिए परिवर्तन पथ का सुझाव दिया गया।

12. उस लेख में हमने नोट किया था कि काफी प्रगति होने के बावजूद, भारत में बैंकिंग का एक पक्ष, जिसका गहन विश्लेषण करने की जरूरत थी, में पर्याप्त बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं उपलब्ध नहीं थी। हमने पाया था कि उस समय देश में कार्यरत 157 घेरलू बैंक 'जिसमें 26 सरकारी क्षेत्र के बैंक, 7 नए निजी क्षेत्र के बैक, 13 पुराने निजी क्षेत्र के बैंक, 43 विदेशी बैंक, 4 स्थानीय क्षेत्र बैक और 64 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं' होने के बावजूद वयस्क लोगों में मात्र 40 प्रतिशत लोगों के पास औपचारिक बैंक खाते हैं। कम आय वाले हाउसहोल्ड को और अधिक औपचारिक बैंकिंग से जोड़ने तथा बैंक रहित क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचने के लिए निरंतर नवोन्मेषी उपाय (माध्यम, उत्पाद, इंटरफेस सहित) करने की जरूरत है।

13. बढ़ी हुई पहुंच में यह सुनिश्चित करना था कि लघु और मध्यम उद्यमों, जो भविष्य में वृद्धि और रोजगार सृजन करने के प्रमुख कारक हो सकते थे, के लिए ऋण लेने की पहुंच में विस्तार हुआ है। एसएमई को ऋण उपलब्ध करने के लिए बैंकों, निजी इक्विटी के नवोन्मेषी संयोजन की जरूरत पड़ेगी।

14. हमने कहा था कि वित्तीय क्षेत्र का विस्तार होने से कुछ बैंक क्षेत्र विशेष में परिचालन करने हेतु चुन सकते हैं ताकि वे कारोबार को मैनेज करने और जोखिम प्रबंधन के संबंध में कतिपय स्पष्ट लाभ उठा सके। जैसा कि हमने नोट किया है कि कुछ देशों में विशिष्ट श्रेणी के बैंक को लाइसेंस देने की प्रणाली है जहां विशिष्ट श्रेणी के लाइसेंस जारी किए गए हैं, विशेष रूप से, निर्धारित गतिविधियों को करने के लिए प्रतिष्ठानों को लाइसेंस प्रदान किए गए। भारत में वित्तीय क्षेत्र व्यापक और गहन होने से हमने देखा है कि बैंक उस स्थिति को छोड़ आए हैं जहां सभी बैंक सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान करते थे और ऐसी स्थिति में आ गए है कि वे विशिष्ट सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और वह भी मुख्य रूप से अपने चुने हुए क्षेत्र विशेष से संबंधीत सेवाएं ही प्रदान कर रहे हैं।

15. सितंबर 2015 में वित्तीय समावेशन से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए लघु कारोबार और कम आय वाले हाउसहोल्डों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाओं पर श्री नचीकेत मोर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने देश में बैंकिंग प्रणाली का अभिन्न अंग- भुगतान, जमा और ऋण आधार पर दो व्यापक स्वरूप - हॉरिजेंटली डिफ्रेंशिएटेड बैंकिंग सिस्टम (एचडीबीएस) और वर्टिकली डिफ्रेंशिएटेड बैंकिंग सिस्टम (वीडीबीएस) प्रस्तुत किए हैं।

16. एचडीबीएस स्वरूप में, बुनियादी डिजाइन मूलतत्व पूर्ण-सेवा बैंक बना रहा, जिसमें सभी तीनों मूलभूत अंग अर्थात भुगतान, जमा और ऋण शामिल हैं किंतु आकार अथवा भूगोल अथवा क्षेत्रगत जोर के आधार पर भिन्न-भिन्न है। वीडीबीएस डिजाइन में, पूर्ण सेवा बैंक को मूलभूत अंग भुगतान, जमा और ऋण में से किसी एक अथवा एक अधिक में विशिष्ट होने से बदल दिया गया। अन्य के साथ-साथ, समिति ने विशिष्ट श्रेणी के बैंकों के लिए भुगतान बैंक और थोक (होलसेल) बैंक के लाइसेंस देने का सुझाव दिया है।

17. नचीकेत मोर समिति की राय थी कि भारतीय संदर्भ में, भुगतान, बचत और ऋण के लिए स्वतंत्र रूप से (वर्टिकली डिफ्रेंशिएटेड बैंकिंग सिस्टम) विनियामक रियायत होना जरूरी है और उन्हें एक साथ तब लाया जाए जब कुशलता लाभ बहुत अधिक हो और अन्य लागत कम हो।

18. इन सभी सिफारिशों और चर्चा पत्र में प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विशिष्ट श्रेणी के बैंकों को लाइसेंस प्रदान करना एक अपेक्षित कदम है और तदनुसार नवंबर 2014 में हमने विशिष्ट श्रेणी के इन दो प्रकारों अर्थात भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक के लिए लाइसेंस प्रदान करने की घोषणा की थी।

भुगतान बैंक

19. भुगतान प्रणाली का विस्तार उस क्षेत्र में हो रहा है जहां नए विचार, उत्पाद और सेवाओं का शुभारंभ सफलतापूर्वक किया गया है। तत्काल सकल भुगतान (आरटीजीएस), राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली, प्रीपेड और पोस्टपेड लिखतों, कार्ड उपस्थित और अनुपस्थित लेनदेन, विभिन्न प्रकार के ई-वालेट और मोबाइल बैंकिंग उत्पादों के शुरू होने से हम अपने देश में भुगतान क्रांति का अनुभव कर रहे हैं।

20. अगला सबसे अधिक योगदान देने वाला कारक भुगतान बैंक होने जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले, रिज़र्व बैंक ने भुगतान बैंक खोलने के लिए 11 प्रतिष्ठानों को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है। भुगतान बैंक वित्तीय समावेशन के लिए रिज़र्व बैंक के परिवर्तनकारी नवेन्मेषी विनियामक प्रयासों का हिस्सा है जिससे समावेशी वृद्धि को बल मिलेगा। इन बैंकों में वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए विशेष अधिदेश के साथ संरचित किए गए हैं। भुगतान बैंक के लाइसेंस संबंधित दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि भुगतान बैंकों की स्थापना का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना है : रणनीति निम्नलिखित के लिए होगी : (i) लघु बचत खाता और (ii) प्रवासी श्रमिक बल, कम आय वाले हाउसहोल्ड, लघु कारोबारी, अन्य असंगठित क्षेत्र के प्रतिष्ठान और अन्य प्रयोक्ताओं को भुगतान/विप्रेषण सेवाएं। भुगतान बैंक को निम्नलिखित गतिविधियां करने की अनुमति है:

ए. मांग जमा स्वीकार करने के संबंध में, भुगतान बैंक को अभी फिलहाल, प्रति ग्राहक अधिकतम ₹100,000 रखने की अनुमति है।

बी. एटीएम/डेबिट कार्ड जारी करना।

सी. विभिन्न माध्यमों के जरिए भुगतान और विप्रेषण सेवाएं।

डी. अन्य बैंक के बीसी और

ई. म्युचुअल फंड यूनिट और बीमा उत्पाद इत्यादि जैसे गैर-जोखिम साझा करने वाले साधारण वित्तीय उत्पादों का संवितरण।

21. जैसा कि आप देख सकते हैं कि वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के प्राथमिक उद्देश्य को ध्यान में रखकर इसका सृजन किया गया है। हमने इस बात पर भी जोर दिया है कि भुगतान बैंक पूरी तरह से कंप्यूट्रीकृत और प्रौद्योगिकी संचालित संस्था होने चाहिए। आप इस बात की सरहना जरूर करेंगे कि यदि आपको याद होगा कि जब हमने 1993 में नए बैंकों के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए नीति संबंधी दिशानिर्देशों की घोषणा की थी, तो एक जरूरत यह थी कि ये शुरू से प्रौद्योगिकी संचालित बैंक होने चाहिए और जिसका परिणाम सूचना प्रौद्योगिक आधार बैंकिंग का नया युग है जिसका लाभ देश बीस साल पहले भी उठा सकता था। इसी तरह, हमें विश्वास है कि भुगतान बैंक आगे भुगतान के क्षेत्र में क्रांति लाएंगे।

22. कुछ दिन पूर्व, किसी ने भुगतान बैंकों के उद्भव की तुलना में टेलीकाम टावर्स के उद्भाव से की थी। उसने टेलीकाम उद्योग में कहा था कि प्रत्येक टेलीकाम ने शुरूआत में अपने स्वयं के टावर प्रणाली विकसित की थी और इससे यह अधिक लागत वाला वेंचर बन गया था और वृद्धि एक समूह विशेष तक सीमित थी। तब उसके बाद एक समय ऐसा आया जब टेल्को को टावर इन्फ्रास्ट्रक्चर से अलग कर दिया और टावर एक बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर बन गया जहां सभी टेलीकाम कंपनी इसका उपयोग कर सकती थीं। इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं मोबाइल सेवाओं का बहुत विस्तार हुआ, जिसमें कम और वहन की जाने योग्य लागत पर लगभग सभी लोगों को मोबाइल सेवाएं उपलब्ध हो सकीं, इसकी गुणवत्ता और सुविधिओं में लगातर सुधार हो रहा है। इसी तरह, हम भुगतान बैंक के आगमन से देख सकते हैं, यूनिवर्सल बैंक को भुगतान इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत अधिक व्यय करना पड़ सकता है जिसमें अधिक लागत पर जगह और आस्तियां और

साझा, प्रौद्योगिकी आधारित कम लागत वाले भुगतान इन्फ्रास्ट्रक्चर पर निर्भरता, जिसका संचालन भुगतान बैंकों द्वारा किया जाएगा, शामिल हैं, और इससे वंचित लोगों में बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाने में बहुत अधिक वृद्धि हो सकती है। इससे वित्तीय समावेशन होगा और समावेशी वृद्धि होगी।

लघु वित्त बैंक

23. समावेशी वृद्धि के लिए एक समान परिवर्तनकारी नमोन्मेषी परिवर्तन से लघु वित्त बैंकों की शुरूआत होगी। जैसा कि हमने पूर्व में उल्लिखित बैंकिंग संरचना पर अपने चर्चा पत्र में पाया है कि देश-स्तर के अध्ययन से पता चलता है कि लघु बैंक बड़े बैंकों की तुलना में अलग ढंग से कार्य निष्पादन करें। स्थानीय जानकारी के लिए अधिक पहुंच, स्थानीय संपन्नता के लिए अधिक प्रतिबद्धता, लागत और जोखिम प्रबंधन में अंतर और प्रतिस्पर्धा नीति से स्थानीय आर्थिक विकास पर इस प्रकार के बैंकों के विशेष प्रभाव का पता चल सकता है। विकासशील देशों में, जहां आर्थिक विकास ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं की कम और अपर्याप्त पहुंच के कारण प्रभावित हुआ है, वहां, लघु बैंक लघु और मझोले आकार वाले उद्यमों को वित्तपोषण देने के अवसरों को बढ़ा सकते हैं और उद्यमवृत्ति को बढ़ावा दे सकते हैं।

24. परिणाम स्वरूप, नवंबर 2014 में हमने घोषणा की थी कि एक नए प्रकार के विशिष्ट बैंक, लघु बैंकों को लाइसेंस की मंजूरी प्रदान करेंगे। लघु वित्त बैंकों जैसे कि भुगतान बैंकों की स्थापना का उद्देश्य भी वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना है: तथापि, इसे भिन्न प्रकार की रणनीतियों के जरिए प्राप्त करने का प्रयास किया गया है : (i) मुख्यतः सेवाओं से वंचित और आंशिक रूप से सेवाएं पा रहे लोगों को बचत माध्यम का प्रावधान (ii) लघु कारोबार इकाइयों : लघु और अतिलघु किसानों: सूक्ष्म और लघु उद्योगों; और असंगठित क्षेत्र के अन्य प्रतिष्ठानों को श्रेष्ठ प्रौद्योगिकीजन्य कम लागत परिचालन पर ऋण उपलब्ध कराना।

25. कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि लघु वित्त बैंक अथवा भुगतान बैंक विशिष्ट प्रकार के बैंकों का पहला प्रकार नहीं है; देश में सफलता की मात्रा पर मतभेद होने के साथ ही प्रयास और परीक्षण किया गया था, विशिष्ट श्रेणी के बैंक और विशेष रूप से लघु बैंक उस समय नाम नहीं किए गए किंतु 1974 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 1996 में स्थानीय क्षेत्र बैंक खोले गए थे। तथापि, इन लघु बैंकों में वित्तीय समावेशन करने की क्षमता थी, किंतु आरआरबी और एलएबी का कार्यनिष्पादन संतोषजनक नहीं रहा। इस प्रकार के लघु बैंकों के कारोबार मॉडल में सीमित पूंजी आधार, प्रतिबंधित भौगिलिक क्षेत्राधिकार, निधि स्त्रोतों का विविधीकरण और संकेद्रण जोखिम जैसी अंतर्निहित बुनियादी कमजोरियां हैं।

26. इसलिए, जैसा कि आप देखेंगे कि हमने सावधानीपूर्वक लघु वित्त बैंक के विस्तार की रूपरेखा तैयार की है जिसमें वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने का उद्देश्य शामिल है जिससे समावेशी वृद्धि की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। जिस उद्देश्य के साथ लघु वित्त बैंक की स्थापना की जाएगी, उनमें लघु वित्त बैंक का मुख्य उद्देश्य सेवाओं से वंचित और आंशिक रूप से सेवाएं पा रहे लोगों, जिसमें लघु कारोबार इकाइयां, लघु और अतिलघु किसान, सूक्ष्म और लघु उद्योग और असंगठित क्षेत्र के अन्य प्रतिष्ठान शामिल हैं, की जमाराशियों को स्वीकार करना और ऋण देने की बुनियादी बैंकिंग गतिविधियों को करना है। इसके अतिरिक्त ये बैंक अन्य गैर-जोखिम वाली साधारण वित्तीय सेवाओं की गतिविधियां, म्युचुअल फंड इकाई, बीमा उत्पाद, पेंशन उत्पाद इत्यादि जैसे निजी फंड की किसी प्रतिबद्धता की अपेक्षा न रखने वाली गतिविधयों को रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन और इस प्रकार के उत्पादों के लिए क्षेत्रगत विनियामक की जरूरतों का अनुपालन करने के बाद कर सकते हैं। लघु बैंक अपने ग्राहकों की जरूरत के लिए विदेशी मुद्रा कारोबार में प्राधिकृत व्यापारी वर्ग II भी हो सकते हैं। लघु वित्त बैंक के लिए परिचालन क्षेत्र की सीमा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उम्मीद है कि लघु वित्त बैंक मुख्यतः स्थानीय जरूरतों को पूरा करेंगे।

27. इन्हें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र क्षेत्रों के अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 75 प्रतिशत हिस्सा देना होगा। जहां, मौजूदा पीएसएल दिशा-निर्देशों के अनुसार इन्हें अपनी एएनबीसी का 40 प्रतिशत हिस्सा पीएसएल के अंतर्गत भिन्न-भिन्न उप क्षेत्रों में देना चाहिए, वहीं पीएसएल जहां इनहें प्रतिस्पर्धी लाभ हो, वहां पीएसएल के तहत किसी एक अथवा अन्य उप क्षेत्रों में 35 प्रतिशत हिस्सा आबंटित कर सकते हैं।

28. एकल और समूह बाध्यताकारी के लिए अधिकतम ऋण सीमा और निवेश सीमा क्रमशः उनकी पूंजीनिधि की 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत होगी। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक मुख्यतः छोटे कारोबारियों को ऋण देता है, इसलिए बैंकों को अपने ऋण संविभाग का कम से कम 50 प्रतिशत में ₹2.5 मिलियन तक के ऋण और अग्रिम होने चाहिए।

29. ये लघु वित्त बैंक कैसे अहम होने जा रहे हैं? मैं इस पर अपने विचार रखना चाहता हूँ। पहला, हमने लघु वित्त बैंक बनाने के लिए किन्हें लक्ष्य कर रहे हैं? लघु वित्त बैंकों को लाइसेंस देने संबंधी दिशा-निर्देशों से पता चलता है कि बैंकिंग और वित्त में 10 वर्षों का अनुभव रखने वाले प्रवासी लोगों/व्यवसायियों तथा प्रवासी लोगों के स्वामित्व और नियत्रंण वाली कंपनियां और सोसाइटी लघु वित्त बैंक को स्थापित करने के लिए प्रमोटर के रूप में पात्र होंगे। दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि मौजूदा गैर बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी), सूक्ष्म वित्त कंपनियां (एमएफआई) और एलएबी जो प्रवासी लोगों के स्वामित्व और नियंत्रण में हैं, भी लघु वित्त बैंक में परिवर्तित होने के लिए चुन सकते हैं। हमें 72 आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं और जैसा कि आपने नोट किया होगा कि उनमें से 41 आवेदन मौजूदा एनबीएफसी, एमएफआई और एलएबी के हैं और 12 आवेदन वैयक्तिकों/पेशेवरों से प्राप्त हुए हैं। हमारे पास पंजीकृत एमएफआई-एनबीएफसी 65 हैं और उनके स्रोत उनकी इक्विटी, बैंकों से उधारी और बाजार उधारी तक सीमित हैं। उन्हें कम लागत वाली अथवा किसी प्रकार की जमारशि लेने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार की बाधाओं के बावजूद, उनके पास 25.5 मिलियन खाता/ग्राहक हैं और मार्च 2015 के अंत तक ₹277.34 बिलियन का ऋण संविभाग पोर्टफोलियो है। इसी तरह, एनबीएफसी भी अपने स्रोतों के लिए अपनी इक्विटी, बैंक वित्त और बाजार उधारी पर निर्भर है। मार्च 2015 के अंत की स्थिति के अनुसार 11,842 पंजीकृत एनबीएफसी में से अधिकांश 11,622 एनबीएफसी जमा स्वीकार नहीं कर सकती है। इन एनबीएफसी का ऋण पोर्टफोलियो मार्च 2015 के अंत में ₹11,169.24 बिलियन रहा। अब तक, एलबीएस को उन जिलों, जहां उन्हें सेवाएं प्रदान करने की अनुमति प्रदान की है, के बाहर अपनी सेवाओं का विस्तार नहीं कर सकते हैं। मार्च 2015 के अंत में उनका ऋण पोर्टफोलियो ₹13.18 बिलियन रहा। ये संस्थाएं वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में हैं - परिभाषा के अनुसार एमएफआई और सेवाओं से वंचित अथवा कम सेवाएं पा रहे लोगों और अर्थव्यवस्था को सेवा प्रदान करने के जरिए एनबीएफसी और एलएबी। यदि ये एमएफआई, एनबीएफसी और एलएबी इस बाधाओं के साथ जिसमें वे अपना परिचालन करते हैं, इस स्तर का विस्तार कर सकते हैं, यदि इस प्रकार की स्थापित संस्थाएं लघु वित्त बैंक बन जाए, तो कम लागत वाली जमाराशिओं को स्वीकार करने, अखिल भारतीय परिचालन और बैंक व्यवस्था के चलते ये सेवाओं से वंचित लोगों अथवा कम सेवा पा रहे लोगों और इस व्यवस्था में शामिल न किए गए लोगों को कहीं अधिक सेवाएं प्रदान कर सकती हैं। घर पर सेवाएं, अनुकूल समय, नकदी प्रवाह आधारित ऋण का मूल्यांकन, न्यूनतम दस्तावेज, सतत निगरानी, हैंड-हेल्ड मैनुअल एटीएम आदि सुविधाएं होने से ये लघु वित्त बैंक बैंकिंग के स्वरूप और परिभाषा को पूरी तरह बदल सकते हैं। इनकी सफलता के बाद, मुझे विश्वास है कि पाठ्य पुस्तकें बैंकिंग अवधारणा को फिर से परिभाषित करेंगी, जिसमें पारंपरिक बैंकिंग के अलावा इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली को भी शामिल किया जाएगा।

अवांछनीय और आपत्तिजनक परिवर्तनकारी नवोन्मेष

30. अभी तक हमने उन नवेन्मेषी उपायों पर चर्चा की है जिनका हम समर्थन करते हैं, हमें कतिपय अन्य नवोन्मेषी उपायों पर भी चर्चा करने की जरूरत है जिनमें परिवर्तनकारी क्षमता है, किंतु उतना वांछनीय अथवा अपत्तिजनक, अथवा प्रासंगिक नहीं है किंतु फिर भी, कम से कम उनकी सावधानीपूर्वक निगरानी करने और उनके प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। विशेष रूप से, मैं दो गतिविधियों की चर्चा करना चाहता हूँ- डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी और क्राउडफंडिंग।

31. क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल करेंसी है जिसमें करेंसी की इकाइयों के सृजन का विनियमन और निधि अंतरण का सत्यापन करने के लिए इंक्रिप्शन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है और इसका परिचालन किसी केंद्रीय बैंक से अलग स्वतंत्र रूप से होता है।

32. क्राउडफंडिंग क्या है? क्राउड फंडिंग फंड जुटाने की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें तहत किसी परियोजना अथवा किसी वेंचर के लिए इंटरनेट के जरिए अनेक लोगों से फंड जुटाया जाता है। क्राउड फंडिंग वैकल्पिक वित्त का एक रूप है जो कि परंपरागत वित्तीय प्रणाली से बाहर विकसित हुआ है।

33. क्या ये भी परिवर्तनकारी नवोन्मेषी उपाय समावेशी वृद्धि के लिए हैं? असामान्य तरीके से ये दोनों गतिविधियां प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर आधारित हैं, इसीलिए, ये नवोन्मेषी हैं : ये गतिविधियां उन मानक तरीकों को नुकसान पहुंचा सकती हैं जिसमें मुद्रा और उधार प्रणाली परिचालित होती है, और इसीलिए ये परिवर्तनकारी हैं। क्या ये गतिविधियां वित्तीय समावेशन के लिए सहायक हैं? हां, जरूर हैं: ये दोनों गतिविधियां वित्तीय समावेशन में सहयोग कर सकती हैं और इसलिए समावेशी वृद्धि के लिए भी सहायक हैं। क्रिप्टो करेंसी उन गतिविधियों में सहयोग कर सकती हैं जो सामान्य तरीकों में इस प्रकार के लेनदेनों का निपटान करने में कठिनाइयां महसूस करती हैं। क्राउडफंडिंग से उन जरूमंद व्यक्तियों और संस्थानों को फंड जुटाने में मदद मिल सकती है, जिन्हें फंड की जरूरत होती है और इस तरह के फंड में क्राउडफंडिंग कॉल का केवल वे लोग/प्रतिष्ठान ही जवाब देते हैं जो इस तरह के लोगों और प्रतिष्ठानों की मदद करने की इच्छा रखते हैं। इस तरह से दोनों ही वित्तीय समावेशन में सहयोग करते हैं।

34. तब फिर, मैं क्यों कहता हूँ कि ये वांछनीय नहीं हैं? मैं क्यों कहता हूँ कि ये आपत्तिजनक हैं? एक बात यह भी है कि ये दोनों विनियामक मुक्त परिवेश में कार्य करने की आशा करते हैं। वित्तीय मामलों में, अनेक देशों में माना गया है कि अविनियमित वित्तीय प्रणाली में आम लोगों को उनकी गाढ़ी कमाई से वंचित रहने की संभावना बहुत होती है और इसीलिए इस प्रकार की गतिविधियों को अनुमति देना भी बहुत जोखिम भरा है। इतना ही नहीं, इसमें कोई प्रवर्तक भी नहीं है। यह बहुत ही जोखिम भरा है विशेष रूप से, जब इस प्रकार की प्रणाली का परिचालन अंतरराष्ट्रीय रूप से भी होता है। यह सही है कि क्राउडफंडिंग में एक ही प्लेटफार्म होगा जिसमें एक प्रवर्तक की भूमिका है। तथापि, इसकी प्रभावकारिता अपत्तिजनक है और अधिकांशतः एक-पक्षीय है। दूसरा, से मनीलांडरिंग, आतंकवाद को वित्तपोषण और कर चोरी जैसी आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को सहयोग कर सकती है। इस संबंध में, हमारे यहां क्राउडफंडिंग का कोई ऐसा मामला दर्ज नहीं किया गया है, किंतु क्रिप्टो करेंसी के बारे में व्यापक स्तर पर सदेंह है कि इसके जरिए आपराधिक गतिविधियों को वित्तपोषित किया गया है। हमें इन गतिविधियों पर सावधानीपूर्वक निगरीनी रखने की जरूरत है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये नवोन्मेषी गतिविधियां जिनमें परिवर्तनकारी क्षमता है, वांछनीय अथवा अपत्तिजनक, उपयुक्त और गुणवत्ता वाली नहीं हो सकती हैं।

समापन

35. निष्कर्ष रूप में, हम कह सकते हैं कि वित्तीय क्षेत्र में अनेक परिवर्तनकारी नवोन्मेषी उपाय वित्तीय समावेशन के जरिए समावेशी वृद्धि को आगे बढ़ा सकते हैं। देश इस प्रकार के श्रम का लाभ उठा रहा है। वित्तीय विनियमन भी परिवर्तनकारी नवोन्मेषी का सहयोगी भी हैं और वे इनका उपयोग भी करते हैं। तथापि, हमें कतिपय अन्य परिवर्तनकारी नवोन्मेशी उपायों के प्रति सजग रहने की जरूरत है जो बहुत ही जोखिमपूर्ण हैं और बैंकिंग प्रणाली को अस्थिर कर सकते हैं।

36. मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद!